

(b) Countries of refinement of gold and origin of watches are the United Kingdom, Switzerland, Germany, France and Japan.

#### World Bank Report on Indian Economy

76. SHRI K.M. KOUSHIK :  
 SHRI NANJA GOWDER :  
 SHRI R.K. AMIN :  
 SHRI N.K. SOMANI :  
 SHRJ J. MOHAMAD IMAM :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the World Bank recently submitted a report for use of the Aid-India Consortium meeting recently held in Paris ;

(b) whether the World Bank in its report *Inter-alia* found that political crisis in India was to quite an extent responsible for stagnation on the economic front ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

#### राज्यों को विशेष सहायता

77. श्री भोला नाथ मास्टर :

श्री विं नरसिंहा राव :

श्री देविन्दर सिंह गार्जा :

क्या वित्त मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाज़ुक वित्तीय स्थिति के कारण

1970-71 में किन-किन राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है और प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गई है;

(ख) यह सहायता किन राज्यों पर दी गई है;

(ग) क्या उक्त सहायता इस बात को ध्यान में रखते हुए दी गई है कि गैर-योजना कार्यों के लिए उनका संसाधन अपर्याप्त है; और

(घ) गैर-योजना कार्यों के लिये संसाधनों की कमी के क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विज्ञा चरण शुक्ल) : (क) और (ख). सम्मिलित प्रश्न का संकेत चालू वित्तीय वर्ष में कुछ राज्यों को (क्रृति के रूप में) दी जाने वाली उस उस विशेष सहायता की ओर है जिसके लिए केन्द्रीय बजट में व्यवस्था की गई है। योजना आयोग के मूल्यांकन के अनुसार जिन राज्यों के संसाधनों में अनिवार्य रूप से कमी होने की संभावना है, इस प्रकार की सहायता केवल उन्हीं राज्यों को दी जाएगी। पिछले वर्ष योजना आयोग ने जो प्रारम्भिक मूल्यांकन किया था उसके अनुसार चालू वर्ष में जिन राज्यों को विशेष सहायता की जरूरत होगी वे हैं—आनंद प्रदेश, असम जम्मू और कश्मीर, केरल भृथ्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। किन्तु अभी अन्तिम रूप से यह निर्णय नहीं किया गया है कि प्रत्येक राज्य का ठीक-ठीक कितनी रकम दी जायेगी तथा दी जाने वाली सहायता की राशि क्या होगी।

(ग) और (घ). इस व्यवस्था के अन्तर्गत, सरकार ने सिद्धांत यह बात स्वीकार कर ली है कि यह विशेष सहायता उन्हीं राज्यों को दी जाय जिनके साधनों में अनिवार्य रूप से कमी होगी। राज्यों के साधनों में होने वाली इस कमी का निर्वाचण योजना आयोग द्वारा